करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

सितंबर 2021

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **5**

- दिल्ली एनसीआर में दो ज़िलों को शामिल करने संबंधी ड्राफ्ट तैयार 5
- प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना 5
- ललितपुर में बनेगा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा 6
- गन्ना एसएपी में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी सरकार 6
- स्वच्छता महाभियान 7
- उत्तर प्रदेश की पहली प्राइवेट कृषि मंडी 7
- राष्ट्रीय पोषण माह 7
- सभी आईटीआई में लगेंगे सोलर पॉवर प्लांट 8
- श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आस-पास 10वर्ग किमी. क्षेत्रफल तीर्थ स्थल घोषित 8
- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय तथा एडवोकेट चैंबर व मल्टीलेबल पार्किंग 9

नोट :

- कोरोना की स्वदेशी दवा 'उमीफेनोविर' 9
- अलीगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास 9
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 10
- मथुरा में पेप्सिको फूड्स प्लांट 10
- उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड गठित 11
- फोर्टिफाइड चावल 11
- गंगा की सांस्कृतिक विरासत की खोज़ एवं संरक्षण 12
- कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का अनावरण 12
- उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका 13
- उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय 13
- बिजनौर में मेडिकल कॉलेज 14
- प्रतिहार शासक मिहिरभोज 14
- यूपीएसबीसी ने अधिकतम संख्या में पुलों का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया 14
- गुलाबी मीनाकारी 15

नोट :

- कैबिनेट विस्तार 15
- बदायूँ से पुरातात्त्विक अवशेषों की प्राप्ति 15
- मेडिकल डिवाइस पार्क 16
- उत्तर प्रदेश में गन्ने से इथेनॉल उत्पादन 16
- मुख्यमंत्री ने 1.23 लाख आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को स्मार्ट फोन बाँटे 17

दृष्टि The Vision

नोट :

उत्तर प्रदेश

दिल्ली एनसीआर में दो ज़िलों को शामिल करने संबंधी ड्राफ्ट तैयार

चर्चा में क्यों ?

- 31 अगस्त, 2021 को योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के शामली और मुज़फ्फर नगर ज़िलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल करने से संबंधित ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस ड्राफ्ट की घोषणा नई दिल्ली के निर्माण भवन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 40वीं बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार, हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में हुई।
- इस घोषणा के साथ ही यमुना एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) को भी मेट्रो सेंटर घोषित किया गया है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के बीच बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिये कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट भी साइन किया गया। इससे इन राज्यों के एनसीआर क्षेत्र में बिना किसी रूकावट के आवागमन संभव हो सकेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना

चर्चा में क्यों ?

- 1 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 5.51 लाख लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबियाँ सौंपी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने अयोध्या, सोनभद्र और रायबरेली के पाँच लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाबियाँ सौंपी, जबकि अन्य लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से चाबियाँ सौंपी गई।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी/ग्रामीण) तथा मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पिछले चार वर्षों में उत्तर प्रदेश में लगभग 42 लाख आवास स्वीकृत किये गए।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड गोला के तहत ग्राम लंदनपुर ग्रंट में विकसित किये गए बाबा गोकर्णनाथ ग्रामीण आवासीय परिसर की कार्य योजना के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन भी किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित कर 52 लाख महिलाओं को स्वरोज़गार से जोड़ा गया है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य की लगभग 70 प्रतिशत आवासों का मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' का शुभारम्भ 20 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से किया गया था।

ललितपुर में बनेगा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

चर्चा में क्यों ?

- 2 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित ललितपुर ज़िले में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने यह फैसला ललितपुर में स्थापित किये जा रहे ड्रग पार्क और बुंदेलखंड में विकसित किये जा रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को देखते हुए लिया है।
- उन्होंने कहा कि ललितपुर में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौर की एक हवाई पट्टी थी, जिसे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा।
- पहले चरण में इस हवाई अड्डे को छोटे विमानों की लैंडिंग के लिये तैयार किया जाएगा और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा।
- ललितपुर में एयरपोर्ट की स्थापना के लिये वहाँ के दो गाँवों से कुल 91.773 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी जाएगी। ज़मीन की कुल कीमत 86.65 करोड़ रुपए है।
- रक्षा मंत्रालय के पास 12.79 हेक्टेयर भूमि है, जिसे राज्य सरकार परियोजना के लिये लेगी और बदले में ग्राम समाज की उतनी ही भूमि रक्षा मंत्रालय को देगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च, 2021 में ललितपुर में बंडई बाँध परियोजना के शुभारंभ के दौरान इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा की थी।

गन्ना एसएपी में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी सरकार

चर्चा में क्यों ?

- 3 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार जल्द ही नवंबर से शुरू होने वाले अगले गन्ना पेराई सत्र के लिये गन्ने के राज्य सलाहकार मूल्य (State Advisory Price- SAP) में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने कहा कि वर्तमान में गन्ने की प्रारंभिक किस्म के लिये गन्ना SAP 325 रुपए प्रति क्विंटल और अस्वीकृत किस्म के लिये 315 रुपए प्रति क्विंटल है।
- गौरतलब है कि योगी सरकार ने अक्तूबर 2017 में गन्ना पेराई सत्र 2017-18 के लिये एसएपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी। हालाँकि पिछले तीन वर्षों से, चीनी उत्पादन में वृद्धि के कारण SAP में वृद्धि नहीं की गई है, जो कि महामारी के कारण वर्ष 2020 में मांग में भारी गिरावट के साथ युग्मित है।
- उन्होंने कहा कि देश भर में गन्ना पेराई व गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। साथ ही इथेनॉल के उत्पादन में भी नंबर एक है।
- इस सत्र में 4,289 लाख मीट्रिक टन गन्ने की रिकॉर्ड पेराई की गई है। पहले गन्ने की खेती का रकबा 20 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 28 लाख हेक्टेयर हो गया है।
- मंत्री राणा ने कहा कि योगी सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराया और इसके जरिये 35 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार दिया गया।
- साथ ही उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने चार वर्ष में अब तक गन्ना किसानों को 1,42,311 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

स्वच्छता महाभियान

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जनपद के रैंपस स्कूल, शाहपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में एक सप्ताह तक संचालित होने वाले 'स्वच्छता महाभियान' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोगों- इंसेपेलाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, डायरिया आदि की रोकथाम के लिये इस स्वच्छता महाभियान का शुभारंभ किया गया है।
- इसमें सफाई, जलनिकासी, सेनिटाइजेशन, फॉगिंग, छिड़काव जैसे कार्य किये जाएँगे। साथ ही पेयजल की शुद्धता का ध्यान रखने के लिये क्लोरीन की टेबलेट भी वितरित की जाएँगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1977-78 से 2017 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बड़ी संख्या में बच्चे इंसेफेलाइटिस के कारण जान गँवा देते थे, परंतु वर्ष 2014 में शुरू हुए 'स्वच्छ भारत अभियान' के कारण इंसेपेलाइटिस से होने वाली मौत न्यूनतम स्तर पर है और यह बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाईकर्मियों को उपहार व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने स्वच्छता महाभियान में शामिल सफाईकर्मियों की टोली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उत्तर प्रदेश की पहली प्राइवेट कृषि मंडी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में दिव्या भूमि एग्रीक्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी ने आगरा-ग्वालियर हाईवे पर नगला वोरई गाँव में मंडी बनाने का प्रस्ताव दिया है, इसके बन जाने के बाद यह उत्तर प्रदेश का पहला एफपीओ बाज़ार होगा।

प्रमुख बिंदु

- निजी मंडी आगरा-ग्वालियर राजमार्ग पर 4,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में स्थापित की जाएगी।
- यह बाज़ार 600 किसानों के एक समूह द्वारा संचालित किया जाएगा, जिससे आगरा और उसके आसपास के ज़िलों में कृषि व्यवसाय में सुधार आएगा।
- इस बाज़ार से आगरा-ग्वालियर राजमार्ग के किनारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के 30 किलोमीटर क्षेत्र में फैले 40 गाँवों के किसानों को उपज खरीदने और बेचने का मौका मिलेगा।
- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कृषि उपज मंडी नियमावली में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति या एफपीओ बाज़ार लगाकर क्षेत्रीय किसानों की उपज को खरीद और बेच सकता है।

राष्ट्रीय पोषण माह

चर्चा में क्यों ?

- 7 सितंबर, 2021 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चौथे 'राष्ट्रीय पोषण माह' का शुभारंभ किया तथा आईसीडीएस विभाग के गोद भराई कार्ड 'शगुन' और एक शुभंकर 'आंचल' का विमोचन भी किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषण माह को चार श्रेणियों में बाँटकर संचालित किया जाएगा। पहले सप्ताह में पोषण वाटिका पर पौधारोपण, दूसरे सप्ताह में आंगनबाड़ी लाभार्थियों को पोषण किट वितरण, तीसरे सप्ताह में योग और आयुष तथा चौथे सप्ताह में सैम बच्चों की पहचान एवं उनके लिये सामुदायिक रसोई के निर्माण का विशेष अभियान प्रदेश में चलाया जाएगा।

- राष्ट्रीय पोषण माह, 2021 में पोषण वाटिका की स्थापना हेतु पौधरोपण अभियान तथा अतिकुपोषित-कुपोषित (सैम-मैम) बच्चों के चिह्नांकन एवं अनुश्रवण पर विशेष बल दिया जाएगा।
- इनके अलावा योग एवं आयुष (बच्चों, किशोरी, बालिकाओं तथा महिलाओं को केंद्रित करते हुए योग सत्रों का आयोजन) तथा पोषण संबंधी प्रचार-प्रसार सामग्री व अनुपूरक पुष्टाहार आदि का वितरण किया जाएगा।
- इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य के 24 ज़िलों में निर्मित 529 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया।
- इसके अलावा उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं, मुख्य सेविकाओं एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया तथा 91 नव-चयनित बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से प्रतीकात्मक तौर पर 10 को नियुक्ति-पत्र वितरित किया।
- उल्लेखनीय है कि सामुदायिक लामबंदी सुनिश्चित करने और लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिये हर साल सितंबर महीने को पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी।

सभी आईटीआई में लगेंगे सोलर पॉवर प्लांट

चर्चा में क्यों ?

- 9 सितंबर, 2021 को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (Industrial Training Institutes- ITIs) में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के 66 आईटीआई में 40-40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।
- प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के आईटीआई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाएंगे, जहाँ निर्बाध विद्युत आपूर्ति से विद्यार्थियों को उनके प्रायोगिक कार्यों में सुविधा होगी।
- इसके द्वारा न सिर्फ बिजली की बचत होगी, बल्कि निर्बाध बिजली आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।
- इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आईटीआई को सबसे अधिक लाभ होगा।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य द्वारा संचालित 300 आईटीआई हैं। इन आईटीआई में सीटों की संख्या 1.19 लाख से अधिक है। हाल ही में 44 नए राज्य आईटीआई को शुरू किये गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 58,000 से अधिक सीटों की वृद्धि हुई है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आस-पास 10वर्ग किमी. क्षेत्रफल तीर्थ स्थल घोषित

चर्चा में क्यों ?

- 10 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्म स्थान के 10 वर्ग किमी. के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस घोषित 10 वर्ग किमी. की परिधि में मथुरा-वृंदावन नगर-निगम के 22 वार्ड आएंगे, जिनमें से 7 वार्ड पहले से ही तीर्थ स्थल हैं।
- इसके अतिरिक्त गोवर्द्धन, गोकुल, नंदगाँव, राधाकुंड, बलदेव एवं बरसाना को सरकार ने अप्रैल 2018 में तीर्थ स्थल का दर्जा दिया था।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय ब्रज क्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय तथा एडवोकेट चैंबर व मल्टीलेबल पार्किंग

चर्चा में क्यों ?

- 11 सितंबर, 2021 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज तथा 640.37 करोड़ रुपए की धनराशि से निर्मित होने वाले एडवोकेट चैंबर व मल्टीलेबल पार्किंग का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना भी उपस्थित थे।
- राष्ट्रपति ने कहा कि इतिहास की दृष्टि से इलाहाबाद हाईकोर्ट भारत में स्थापित चौथा हाईकोर्ट है एवं न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है।
- उन्होंने ने कहा कि इस उच्च न्यायालय में सन् 1921 में भारत की पहली महिला वकील कॉर्नेलिया सोराबजी को पंजीकृत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, जो महिला सशक्तीकरण की दिशा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भविष्योन्मुखी निर्णय था।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज शिक्षा का भी महत्त्वपूर्ण केंद्र है। विधि विश्वविद्यालय में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, इसके लिये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस विश्वविद्यालय का विजिटर बनाने हेतु एक्ट बनाएँ।
- राष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता स्व. श्री आनंद भूषण के चित्र का अनावरण किया। कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना एवं उसके गौरवशाली इतिहास के बारे में प्रस्तुतीकरण भी किया गया।

कोरोना की स्वदेशी दवा 'उमीफेनोविर'

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा कोविड-19 की स्वदेशी दवा 'उमीफेनोविर' बनाने का दावा किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- दरअसल सीडीआरआई द्वारा किये गए उमीफेनोविर के तीसरे चरण का ट्रायल सफल रहने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि यह दवा कोरोना के हल्के व लक्षणरहित रोगियों के इलाज में बहुत प्रभावी है। साथ ही, उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिये रोगनिरोधी के रूप में उपयोगी है। यह पाँच दिन में वायरस लोड खत्म कर देती है।
- उमीफेनोविर सार्स कोव-2 वायरस के सेल कल्चर को बेहद प्रभावी तरीके से नष्ट करती है एवं मानव कोशिकाओं में इस वायरस के प्रवेश को रोकती है।
- उमीफेनोविर एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरस दवा है, जिसका रूस, चीन सहित अन्य देशों में कई वर्षों से एन्फ्लुएंजा और निमोनिया के लिये एक सुरक्षित दवा के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

अलीगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 14 सितंबर, 2021 को अलीगढ़ के मूसेपुर गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया एवं डिफेंस इंडस्ट्रियल के अलीगढ़ नोड की प्रगति का अवलोकन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा तथा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी व मैनपॉवर के विकास का बड़ा केंद्र बनेगा।
- उल्लेखनीय है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने वर्ष 1915 में काबुल में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया था। इस सरकार में राष्ट्रपति स्वयं राजा महेंद्र प्रताप तथा प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे।
- इसके अलावा 1000 एकड़ में खैर रोड पर अंडाला में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसके विकास की ज़िम्मेदारी यूपीडा को दी गई है।
- उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, ड्रोन, एयरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट, डिफेंस पैकेजिंग के लिये नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, इससे अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र की नई पहचान स्थापित होगी।
- उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा के तहत राज्य के 6 शहरों में रक्षा गलियारा विकसित करने की योजना है। ये छह शहर हैं- लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट एवं झाँसी।

उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना

चर्चा में क्यों ?

- 15 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के उद्देश्य से, एक अनूठी 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना' शुरू करने की घोषणा की, जो आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदार बनाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने यह घोषणा लखनऊ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं ज़िला पंचायतों के तहत विभिन्न सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए की।
- मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों को इस अभिनव योजना के औपचारिक शुभारंभ के लिये एक कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा।
- इस योजना के तहत, प्रत्येक व्यक्ति को गाँवों में बुनियादी ढाँचे के विकास के विभिन्न कार्यों में सीधे भाग लेने का मौका मिलेगा।
- राज्य सरकार परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत वहन करेगी, जबकि शेष राशि इच्छुक लोगों द्वारा दी जाएगी। बदले में, परियोजना का नाम सहयोगियों के रिश्तेदारों के नाम पर उनकी इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना गाँवों में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, अग्निशमन सेवा स्टेशन आदि की स्थापना के लिये एक अच्छा प्रयास हो सकता है।
- मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ और जौनपुर ज़िला पंचायतों में एफडीआर पद्धति से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सड़कों के निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य है।।

मथुरा में पेप्सिको फूड्स प्लांट

चर्चा में क्यों ?

- 15 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में पेप्सिको इंडिया कोसी कलां मथुरा प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश सरकार के सहयोग से पेप्सिको द्वारा कोसी कलां में दो वर्ष से भी कम समय में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है।
- इस प्लांट की स्थापना से 1500 लोगों को प्रत्यक्ष तथा बड़ी संख्या में लोगों को परोक्ष रूप से रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे।

- यह पेप्सिको इंडिया का भारत में स्थापित सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण प्लांट है।
- कार्यक्रम के दौरान पेप्सिको द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म 'उन्नति की साझेदारी' भी प्रदर्शित की गई।
- कोसी कलां में 800 करोड़ रुपए से अधिक लागत से स्थापित इस फूड्स प्लांट यूनिट के माध्यम से डेढ़ लाख मीट्रिक टन आलू का प्रति वर्ष प्रसंस्करण किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है।
- ब्रज क्षेत्र में आगरा एवं अलीगढ़ मंडलों के 8 जनपदों में बड़े पैमाने पर आलू उत्पादन होता है। इस यूनिट की स्थापना इस क्षेत्र के आलू उत्पादक किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ाने में सहायक होगी।

उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड गठित

चर्चा में क्यों ?

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए एक निर्णय के आलोक में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जिसके द्वारा किन्नरों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर काम करते हुए नीतिगत एवं संस्थागत सुधारों के लिये सरकार को सुझाव दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड कुल 23 सदस्यीय संस्था है। इसकी संरचना निम्न प्रकार है-
  - अध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्री
  - उपाध्यक्ष : मुख्यमंत्री द्वारा नामित किन्नर समुदाय का सदस्य
  - सदस्य सचिव : निदेशक, समाज कल्याण विभाग
  - संयोजक : अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
  - सदस्य : 5 किन्नर समुदाय के प्रतिनिधि एवं 2 किन्नर समुदाय के लिये कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधि
  - पदेन सदस्य : विभिन्न विभागों के सचिव एवं लखनऊ पुलिस आयुक्त
- बोर्ड के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा तथा बोर्ड को तीन महीने में एक बैठक करना ज़रूरी होगा।
- इसके अतिरिक्त निदेशक, सामाज कल्याण की अध्यक्षता में एक किन्नर सहयोग इकाई गठित की जाएगी, जो किन्नरों का डाटाबेस तैयार करने के साथ-साथ किन्नरों की समस्याओं को हल करने एवं नीतियों के क्रियान्वयन की समय-सीमा संबंधी रिपोर्ट शासन को सौंपने का कार्य करेगी।
- साथ ही प्रत्येक ज़िले में ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय ज़िला स्तरीय किन्नर सहायता इकाई का गठन होगा, जिसकी बैठक प्रत्येक महीने आयोजित की जाएगी।

फोर्टिफाइड चावल

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली में राशन की दुकानों में मिलने वाले मोटे एवं पीले चावल को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके संदर्भ में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यह फोर्टिफाइड चावल है, न कि प्लास्टिक चावल।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा कुपोषण के समाधान के लिये बाल विकास योजना, मध्याह्न भोजन योजना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जा रहा है।

- इस फोर्टिफाइड चावल में विटामिन B2, B3 एवं आयरन जैसे तत्त्वों को समावेशित किया गया है।
- FSSAI के अनुसार 50 किलोग्राम सामान्य चावल में एक किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल मिश्रित किया जाता है।
- राइस मीलों में चावल की पॉलिश के समय विटामिन B6, B3 एवं विटामिन E जैसे पोषक तत्त्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिये सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावल के वितरण का निर्णय लिया गया है।

गंगा की सांस्कृतिक विरासत की खोज़ एवं संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में गंगा की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों के क्रम में केंद्रीय टीम द्वारा इत्र नगरी 'कन्नौज' में परंपरागत इत्र उद्योग, गट्टा, धार्मिक स्थल, घाट का अध्ययन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि वर्ष 2019 से केंद्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारों पर 51 किमी. दूरी तक अवस्थित प्राकृतिक, स्थापत्य संबंधी एवं अमूर्त विरासतों को संरक्षित करने के उद्देश्य से नमामि गंगा परियोजना के तहत नमामि गंगा सांस्कृतिक दस्तावेज़ीकरण परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।
- नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई एक फ्लैगशिप परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना एवं गंगा नदी का पुनर्जीवन है।
- इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय गंगा परिषद की क्रियान्वयन शाखा है।
- कन्नौज, जिसे भारत की इत्र नगरी कहा जाता है, 7वीं सदी में पुष्यभूति वंश के शासक राजा हर्षवर्द्धन की राजधानी थी। इसके लिये बाणभट्ट द्वारा 'महोदय श्री' संबोधन का प्रयोग किया गया है। हर्षवर्द्धन की मृत्यु के पश्चात् कन्नौज पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र बन गया था।

कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का अनावरण

चर्चा में क्यों ?

- 18 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का जनपद गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत इस मेट्रो ट्रेन का निर्माण पूर्णतया देश में ही किया गया है।
- उन्होंने कहा कि बड़ोदरा के उपक्रम द्वारा कोविड काल की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इस प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन को समय से पहले उपलब्ध कराया गया है।
- आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के चार शहरों- लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो ट्रेन का सफल संचालन किया जा रहा है। कानपुर और आगरा में मेट्रो का कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही पाँच अन्य प्रमुख शहरों- गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झाँसी में मेट्रो के लिये DPR तैयार है या अंतिम चरण में है।
- उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार कानपुर की मेट्रो ट्रेनों में 'रीजेनरेटिव ब्रेकिंग' का फीचर होगा, जिसकी मदद से ट्रेन में लगने वाले ब्रेक्स के माध्यम से 45 प्रतिशत तक ऊर्जा को रीजेनरेट करके फिर से सिस्टम में इस्तेमाल कर लिया जाएगा।
- वायु प्रदूषण को कम करने के लिये इन ट्रेनों में अत्याधुनिक 'प्रॉपल्शन सिस्टम' मौज़ूद होगा। इन ट्रेन में कार्बनडाईऑक्साइड सेंसर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम होगा जो ट्रेन में मौज़ूद यात्रियों की संख्या के हिसाब से चलेगा और ऊर्जा की बचत करेगा।

- ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनें संचारित आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली से चलेंगी। कानपुर मेट्रो ट्रेन की यात्री क्षमता 974 यात्रियों की होगी।
- इन ट्रेन की डिज़ाइन स्पीड 90 किमी./घंटा और ऑपरेशन स्पीड 80 किमी./घंटा तक होगी। ट्रेन के पहले और आखिरी कोच में दिव्यांगजन की व्हीलचेयर के लिये अलग से स्थान होगा। व्हीलचेयर के स्थान के पास 'लॉन्ग स्टॉप रिक्वेस्ट बटन' होगा, जिसे दबाकर दिव्यांगजन ट्रेन ऑपरेटर को अधिक देर तक दरवाज़ा खुला रखने के लिये सूचित कर सकते हैं।
- कानपुर की मेट्रो ट्रेन थर्ड रेल यानी पटरियों के समानांतर चलने वाली तीसरी रेल से ऊर्जा प्राप्त करेंगी, इसलिये इसमें खंभों और तारों के सेटअप की आवश्यकता नहीं होगी और बुनियादी ढाँचा बेहतर एवं सुंदर दिखाई देगा।
- इन ट्रेनों को अत्याधुनिक फायर और क्रैश सेफ्टी के मानकों के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। हर ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे होंगे, जिनका वीडियो फीड सीधे ट्रेन ऑपरेटर और सेंटर सिक्योरिटी रूम में पहुँचेगा।
- इंफोटेंमेंट के लिये हर ट्रेन में एलसीडी स्क्रीन या पैनल्स भी होंगे। टॉक बैक बटन को दबाकर यात्री आपात स्थिति में ट्रेन ऑपरेटर से बात कर सकेंगे। यात्री की लोकेशन और सीसीटीवी की फुटेज सीधे ट्रेन ऑपरेटर के पास मौज़ूद मॉनीटर पर दिखाई देगी।

उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों में आरोग्य वाटिकाएँ बनाने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि आरोग्यवाटिका नवभारत टाइम्स द्वारा प्रारंभ एक विशिष्ट हेल्थ कॉर्नर है, जिसके तहत शहर के विभिन्न पार्कों में उच्च औषधीय गुणवत्ता वाली एवं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली वनस्पति प्रजातियों को लगाया जाएगा, ताकि आमजन अपने आस-पास उपलब्ध पादपों से होने वाले स्वास्थ्य लाभों से परिचित हो सकें।
- सरकार की घोषणा के अनुसार, शिक्षण संस्थाओं में आरोग्यवाटिका बनाए जाने का उद्देश्य औषधीय वनस्पतियों एवं उनके प्रयोग की प्राचीन भारतीय परंपराओं के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करना है।
- सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सबट्रापिकल हॉर्टीकल्चर, लखनऊ के वैज्ञानिक आर.ए. राम के अनुसार, जन सामान्य भी किचन गार्डन और टैरेस गार्डन में घर पर ही औषधीय पौधे उगा सकते हैं तथा इससे उत्पन्न कचरे को खाद में बदला जा सकता है।

उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राज्य संग्रहालय के निदेशक द्वारा बताया गया कि राज्य का पहला जनजातीय संग्रहालय मार्च 2022 तक पूरी तैयार हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'बलरामपुर' ज़िले के थारू प्रधान ग्राम 'इमिलिया कोडर' में थारू जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है।
- सरकार के अनुसार, इस संग्रहालय में थारू जनजाति के उद्विकास से लेकर उनकी संस्कृति, परंपराएँ, धर्म, जीवनशैली आदि सभी आयामों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। साथ ही इनके विकास के लिये वर्ष 1980 में 'थारू विकास परियोजना' प्रारंभ की गई थी।
- उल्लेखनीय है कि थारू जनजातीय समूह उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इस जनजाति के लोग दीपावली को शोकपर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति द्वारा 'बजहर' नामक पर्व मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें 'बदला विवाह' भी प्रचलित है।

बिजनौर में मेडिकल कॉलेज

चर्चा में क्यों ?

- 21 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए बिजनौर में नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने 281 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज का नाम महात्मा विदुर के नाम पर रखे जाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह मेडिकल कॉलेज 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा।
- इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद बिजनौर के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिये दिल्ली, लखनऊ और मेरठ की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा, यह बिजनौर और इसके आसपास के क्षेत्रों की एक बड़ी आबादी को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराएगा।

प्रतिहार शासक मिहिरभोज

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबुद्ध नगर के दादरी में स्थित मिहिरभोज कॉलेज में मिहिरभोज की प्रतिमा का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि राजा मिहिरभोज को लेकर गुर्जर एवं राजपूत समाज के मध्य उन्हें अपना पूर्वज मानने संबंधी विवाद है। मिहिरभोज के गुर्जर या राजपूत होने के संदर्भ में उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों में अरब यात्री सुलेमान का यात्रा वृत्तांत महत्त्वपूर्ण है। इसमें मिहिरभोज को जुज्र अर्थात् गुर्जर बताया गया है।
- उल्लेखनीय है कि मिहिरभोज 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, जिनका साम्राज्य मुल्तान से बंगाल तक एवं कश्मीर से उत्तर महाराष्ट्र तक विस्तृत था।
- मिहिरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। ये विष्णुभक्त थे, अत: विष्णु के सम्मान में वाराह एवं प्रभास जैसी उपाधियाँ धारण की थी।
- मिहिरभोज की उपलब्धियों का वर्णन उनके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है।

यूपीएसबीसी ने अधिकतम संख्या में पुलों का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया

चर्चा में क्यों ?

- 22 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम (UPSBC) ने साढ़े चार वर्षों में सबसे अधिक पुलों का निर्माण करके कीर्तिमान स्थापित किया है।

प्रमुख बिंदु

- उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में राज्य सरकार ने राज्य को फ्लाईओवर और रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) के नेटवर्क के माध्यम से विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जाते हुए रिकॉर्ड समय में 124 पुल, 54 आरओबी और 355 छोटे पुलों का निर्माण किया है।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुल 1,193 नए पुलों के निर्माण पर तेज़ी से काम कर रही है, जिसमें 121 नए आरओबी, 305 बड़े पुल और 767 छोटे पुल शामिल हैं। इनमें से 260 पुल ऐसे हैं, जिनकी आधारशिला सालों पहले पिछली सरकारों ने रखी थी, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।
- इसी तरह जो 124 लंबे पुल बने हैं, उनमें से 89 पुल तथा 54 आरओबी में से 35 आरओबी लंबे समय से अधूरे पड़े थे, जिन्हें पिछली सरकारों के दौरान शुरू किया गया था। नए ब्रिज नेटवर्क के साथ, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक फ्लाईओवर और सुगम यातायात वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा।

गुलाबी मीनाकारी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस एवं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को बनारसी गुलाबी मीनाकारी उपहार भेंट किये गए।

प्रमुख बिंदु

- मीनाकारी, जिसे एनामेलिंग भी कहा जाता है, धातु की सतह पर खनिज पदार्थों को मिलाकर सजाने की कला है। मीनाकारी को भारत में मुगलों द्वारा लाया गया था।
- इस प्रक्रिया का प्राय: कुंदन पर प्रयोग किया जाता है। इसके तहत किसी वस्तु (Article) के एक तरफ पत्थर और माउंट के बीच सोने की परत के साथ बहुमूल्य रत्नों की जड़ावट होती है, जबकि दूसरी तरफ मीना तकनीक से चमकदार परत चढ़ाई जाती है।
- वाराणसी की मीनाकारी उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इसे वर्ष 2015 में भौगोलिक संकेत (G.I. Tag) प्रदान किया गया था।

कैबिनेट विस्तार

चर्चा में क्यों ?

- 26 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए 1 कैबिनेट मंत्री एवं 6 राज्यमंत्री सहित कुल 7 नए मंत्रियों को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों में जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री तथा छत्रपाल सिंह गंगवार, पल्टू राम, संगीता बलवंत, संजीव कुमार, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति को राज्यमंत्री बनाया गया है।
- इस विस्तार से उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या 60 हो गई है, जो उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की अधिकतम संभावित संख्या है।
- उल्लेखनीय है कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा किसी भी राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% तक हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है।

बदायूँ से पुरातात्त्विक अवशेषों की प्राप्ति

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) को उत्तर प्रदेश के बदायूँ ज़िले के खेड़ा जलालपुर गाँव में एक टीले से गुप्त काल के बाद के पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति हुई है।

प्रमुख बिंदु

- गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित खेड़ा जलालपुर गाँव के टीले से हिंदू मंदिर की मूर्तियों के टुकड़े, प्राचीन ईंट प्राप्त हुए हैं। एएसआई के अनुसार ये अवशेष गुप्तकाल के बाद के (7वीं-8वीं शताब्दी के) हैं, जिनका संबंध आज से करीब 1300-1400 वर्ष पहले के समय से है।
- प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद डॉ. बी.आर. मणि के अनुसार बदायूँ पुरातात्त्विक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थल है। यह प्राचीन पांचाल (द्रौपदी की जन्मस्थली) का हिस्सा था। दिल्ली सल्तनत के मामलूक वंश के शासन के दौरान बदायूँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इक्ता थी। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश यहीं का इक्तादार था।
- उल्लेखनीय है कि बदायूँ अब्दुल कादिर बदायूँनी एवं शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जन्मस्थली थी। साथ ही, यह दिल्ली-लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था।

मेडिकल डिवाइस पार्क

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 'प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क योजना' के तहत उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना को सैद्धांतिक मंज़ूरी प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, मेडिकल डिवाइस पार्क को गौतमबुद्ध नगर में स्थापित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि देश में चिकित्सीय उपकरण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये केंद्र सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय द्वारा 'प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क योजना' शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश में 4 पार्कों के निर्माण को सैद्धांतिक मंज़ूरी प्रदान कर दी गई हैं।
- इस योजना के तहत कुल 400 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना की कार्यावधि 2020-21 से 2024-25 तक निर्धारित की गई है।

उत्तर प्रदेश में गन्ने से इथेनॉल उत्पादन

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा ने प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले गन्ना पेराई सत्र से सीधे गन्ने से इथेनॉल का उत्पादन शुरू करेगा। पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिये उपयोग किये जाने वाले इथेनॉल का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पिपराइच चीनी मिल गोरखपुर और बलरामपुर चीनी मिल में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में गन्ने से सीधे इथेनॉल बनाने का फैसला किया था और पिपराइच चीनी मिल में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।
- उत्तर प्रदेश भारत में इथेनॉल का शीर्ष उत्पादक है। यहाँ इथेनॉल का उत्पादन करने वाली 53 डिस्टिलरी हैं और वार्षिक स्थापित क्षमता 158.44 करोड़ लीटर है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश ने 42.70 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया, जो 2020-21 में बढ़कर 99.31 करोड़ लीटर हो गया। उत्तर प्रदेश में 72 डिस्टिलरी हैं, जिनमें 25 स्टैंडअलोन और 47 चीनी मिलों से जुड़ी हैं।
- उन्होंने कहा कि अगले पेराई सत्र 2021-22 के लिये गन्ने के राज्य सलाहकार मूल्य में वृद्धि से किसानों को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ होगा।
- मंत्री राणा ने कहा कि 33,014 करोड़ रुपए की मांग के खिलाफ, चीनी मिलों ने अब तक 2020-21 सीजन के लिये किसानों को 28,015 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 2017 से 2021 तक, इस साल 21 सितंबर तक किसानों को 1.44 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
- उन्होंने आगे कहा कि 2016-17 तक गन्ने की तीन किस्मों की खेती की जाती थी, जहाँ अधिक उपज देने वाली शुरुआती किस्म का हिस्सा केवल 52 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 98 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश में गन्ना उत्पादकता 2016-17 में 66 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर थी, जो 2020-21 में 81.05 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई।
- उद्योग मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान, चीनी मिलों का संचालन बाधित नहीं हुआ और गन्ना, चीनी उत्पादन तथा इथेनॉल के उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा।

मुख्यमंत्री ने 1.23 लाख आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को स्मार्ट फोन बाँटे

- 28 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के 1.23 लाख आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को स्मार्ट फोन और नवजात शिशुओं के विकास स्तर को मापने के लिये आँगनबाड़ी केंद्रों में 1.87 लाख नवजात विकास निगरानी उपकरण (इंफैंटोमीटर) वितरित किये।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट आँगनबाड़ी बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव होगी। स्मार्ट फोन हर बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करेगा, जिससे दैनिक कार्य आसान और पारदर्शी हो जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में घातक वायरल संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये गठित निगरानी समितियों के हिस्से के रूप में, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता चिकित्सा किट प्रदान करने के लिये घर-घर गईं और लोगों को कोविड वैक्सीन के प्रति जागरूक भी किया।
- उन्होंने कहा कि आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं ने ही 'दस्तक अभियान' को सफल बनाया। आज उत्तर प्रदेश ने एंसेपेलाइटिस को 95-97 प्रतिशत तक सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, जिसका श्रेय आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को दिया जाना चाहिये।

दृष्टि The Vision